यह क्षमता नहीं बढ़ेगा, तब तक हम बड़े-बड़े उद्योग नहीं लगा सकते और बड़े उद्योग जब तक नहीं लगें, तो हम बेकार लोगों को नौकरियां नहीं दे सकते ।

अब सवाल आता है कि हमारी जो पावर्टी लाईन ड्रा की हुई है, क्या कभी मंत्री महोदय ने इस पर ध्यान दिया है कि 321 रुपये पर मंथ की इनकम को जो पावर्टी लाईन ड्रा किया है, इस पर किसी भी आदमी की परचेजिंग केपेसिटी निल रहती है, किंतु क्या वह मुझे बता सकते हैं कि एक आदमी एक हजार रुपये जो तनख्वाह लेता है और उसके घर में पांच सदस्य हैं, तो चावल-दाल खाने के बाद उसकी परचेजिंग केपेसिटी क्या रह जाती है ?

परचेजिंग केपेसिटी एक हजार रुपया कमाने वाले की भी नहीं है और पावर्टी लाईन एक हजार रुपये वाले की भी है और वह भी पावर्टी लाईन के नीचे है, जिस आदमी की अपनी रोज की जरूरतमंद चीजों को खाने के बाद कोई पैसा अगर नहीं बच सकता है, तो उसकी परचेजिंग केपेसिटी जब नहीं है, तो वह भी पावर्टी लाईन के नीचे ही आता है । जब तक हम उसकी आर्थिक अवस्था का सुधार नहीं करते हैं, तब तक हम मुल्क में उद्योग नहीं बढ़ा सकते क्योंकि उनकी परचेजिंग केपेसिटी नहीं बढ़ रही है ।

अब मंत्री महोदय से मेरा सवाल यह है कि क्या इस पर कभी कोई विचार किया गया है, कभी देखा गया है कि किस तरह से रूरल मासेज की परचेजिंग केपेसिटी बढ़ाई जाए ?

जिस तरह से पहले मैंने कहा था कि आज तक हम लोगों के मंत्रालयों में कोई भी मंत्रालय इसके लिये सेपरेट नहीं बना है, जो इम्पलायमेंट को मानीटर कर सके कि हर साल कितने लोग बेकार होंगे, उसमें पढ़े-लिखे कितने होंगे और अनपढ़ कितने होंगे औरतें कितनी होंगी और आदमी कितने होंगे, यह प्लानिंग करके और कितने उद्योग भारतवर्ष में लगेंगे ? उसमें स्किलड इलैक्ट्रीशियन, मकैनिकल या दूसरी तरह के स्किलड लोगों की कितनी जरूरत पड़ेगी और अन-स्किलड लोगों की कितनी जरूरत पड़ेगी, उसके हिसाब से उद्योग का विकास करने का कोई मोनिटरिंग सैल बनाया है या कोई अलग मंत्रालय बनाने की सम्भावना है ? ऐसा विचार रखते हुये मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

MESSAGE FROM THE LOK SABHA —Contd.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRl H. HANUMANTHAPPA); The Secretary-General to report a message from ihe Lok Sabha.

II. The Finance (Amendment) Bill, 1987

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following meb-sage received from the Lok Sabha signed by the Secretary-General of the Lok Sabha;

"In accordance with the provisions ot rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha am directed to enclose the Finance (Amendment) Bill, 1987, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 8th December, 1987.

The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

Sir, I lay the Bill on the Table.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION ON POINTS ARISING ONE OF THE ANS ER TO STARRED QUESTION NO. 244 GIVEN IN THE RAJYA SABHA ON 24TH NOVEMBER, 1987 REGARDING UNEMPLOYMENT AMONG YOUTH —Contd.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Shri Pramod Mahajan.

श्री प्रमोद महाजन : उप सभाध्यक्ष जी, परिवार में एक को रोजगार इस प्रकार का आश्वासन देकर सत्ता में आने वाली सरकार बेरोजगारी के प्रति कितनी

[श्री प्रमोद महाजन]

गंभीरता से देखती है यह मूल प्रश्न के उत्तर से झलक रहा है। उत्तर की पहली पंक्ति में सरकार कहती है कि युवाओं की बेरोज़गारी के संबंध में निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है। दूसरी पंक्ति में सरकार कहती है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में बेरोजगारों की अनुमानित संख्या 9 करोड़ 20 लाख होगी जो योजना के अंत तक कुछ कम होने की संभावना है। इतने अधिक प्रश्न के मूल उत्तर में कुछ नहीं कहा है : प्रश्नोत्तर के दौरान जब श्रम मंत्री जेनेवा में थे और इन्फर्मेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग मिनिस्टर राज्य सभा में लेबर में थे तब उन्होंने किस प्रकार के उत्तर दिए हैं इससे यह लगता है कि सरकार स्थिति की गंभीरता को पहचानने से इंकार कर रही है। इसलिए सब से पहले तो मेरा यह प्रश्न होगा कि क्या सरकार बेरोज़गारी की समस्या की गंभीरता को देखते हुए एक ऐसी यंत्रणा के निर्माण पर विचार करेगी जो अत्याधुनिक दृष्टि से हमें नित्य रूप से देश की बेरोज़गारी की स्थिति के संबंध में जानकारी देती रहे ? दूसरा मेरा प्रश्न इससे संबंधित है कि यदि हमें बेरोजगारी के प्रति उदासीनता को सदा के लिए समाप्त करना है तो संविधान में संशोधन कर रोज़गार के अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकार माना जाए। रोज़गार हिन्दुस्तान के युवाओं का जन्म सिद्ध मौलिक अधिकार है। यदि इस प्रकार का रोज़गार सरकार न दे तो बेरोजगार युवाओं को रोज़गार भत्ता देना पड़े इस प्रकार की व्यवस्था इसके अंतर्गत निर्माण हो। इसलिए श्रम मंत्री जी से मैं दूसरा प्रश्न यह करना चाहता हूं कि यदि वह सुन रहे हों तो..?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए संगमा) : बिल्कुल सुन रहे हैं। ....(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : हां, ठीक है, दो काम पर तो दो व्यक्तियों को एक बार सुन सकते हैं। मैं दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि क्या संविधान में संशोधन करके रोज़गार के अधिकार को मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट माना जाएगा और यदि सरकार बेरोज़गारों को रोज़गार न दे तो क्या उन्हें निश्चित रूप से रोज़गार भत्ता मिलेगा ? जैसे और देशों में दिया जाता है। मेरा तीसरा प्रश्न ग्रामीण बेरोज़गारी से जुड़ा है। ग्रामीण विभागों में बेरोज़गारी सब से अधिक है भले हमारी किताबों में वह लिखी न हो। इसको दूर करने की दृष्टि से महाराष्ट्र में गत कुछ वर्षों से ग्रामीण विभाग में बेरोज़गारों के लिए एक रोज़गार गारन्टी योजना चल रही है। यह कहा नहीं जा सकता कि योजना पूर्णतः दोष-रहित है। सुधार की काफी गुंजाइश हो सकती है। यह सच है कि योजना में कुछ मात्रा में भ्रष्टाचार व्याप्त है। फिर भी इसमें दो राय नहीं हो सकतीं कि इस योजना के कारण महाराष्ट्र को ग्रामीण बेरोज़गारी पर नियन्त्रण लाने का एक अच्छा प्रयास हो रहा है। तो मेरा तीसरा प्रश्न यह होगा कि क्या ग्रामीण बेरोज़गारी को समाप्त करने के लिए सरकार महाराष्ट्र के इस प्रयोग का अध्ययन करेगी ? इसके दोष को दूर कर भ्रष्टाचार के रास्तों को बन्द कर सुधारित रूप में महाराष्ट्र की रोजगार गारण्टी योजना को क्या संपूर्ण राष्ट्र में लागू करने की किसी योजना पर सरकार विचार करेगी ?.... **(समय की घंटी)**....

मेरा चौथा प्रश्न औद्योगिक-नीति के संबंध में है। समय के अभाव में इसकी विस्तृत चर्चा असंभव है। लेकिन जिस देश में सिर पर लगाने का तेल टाटा बनाए, खाने का नमक भी टाटा बनाए, जूता टाटा बनाए, सिर से पैर तक हुन टाटा से टाटा तक अगर हो ऐसे देश के नौजवानों का घाटा ही घाटा होने की पूरी संभावना है। इसको देखते हुए नमक से लेकर रेल इंजन तक अगर कुछ गिने-चुने मुट्ठी भर धन्ना सेठों को ही उद्योगों पर नियन्त्रण होगा तो इससे देश की बेरोजगारी कभी हल नहीं होगी। इसलिए मेरा चौथा प्रश्न यह है कि क्या हमारी छोटी छोटी वस्तुएं जो औद्योगिक नीति

में आती हैं, उसके उत्पादन करने पर बड़े उद्योगों में पाबंदी लगाई जाएगी ? और ऐसी हजारों वस्तुओं की सूची बनाई जाएगी, जो केवल छोटे-उद्योगों में ही हो और बड़े उद्योगों को इसमें आने की अनुमति नहीं दी जायगी, क्या इस प्रकार की औद्योगिक नीति बनेगी ?

मैं केवल दो मिनट और लूंगा ।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : नहीं-नहीं एक मिनट में पूरा कीजिए ।

श्री प्रमोद महाजन : अच्छा, ठीक है । पांचवां प्रश्न, इससे यह जुड़ा है कि आद्योगिक नीति में जैसे देश उन्मुक्तियों का प्रचलन है, वैसे ही बहुत छोटी-छोटी बातों पर इस सेक्टरों पर निर्भर होते जा रहे हैं उदाहरण के रूप में सेवो ब्लेड से लेकर आदिदास के बूट तक हर दाढ़ी-बड़ी रहने वाली चीज में हमने विदेशों के साथ तकनीकी समझौता किया है, जिसके कारण देशी उद्योगों पर विपरीत स्थिति हो रही है क्या इसे सरकार बंद करेगी ? ... **(समय की घंटी)** ....

श्री राम अवधेश सिंह : बोलने दीजिए महोदय ।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : इससे आपका समय जाता है ।

श्री राम अवधेश सिंह : जाने दीजिए ।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, अंतिम प्रश्न, मेरा यह होगा कि क्या सरकारी सेवाओं पर अघोषित बंदी सरकार उठा लेगी । आज बेरोजगारों को जब साक्षात्कार के लिए जाना पड़ता है तो उनके पास रेल या बस का भाड़ा देने को पैसे भी नहीं होते । ऐसी स्थिति में क्या साक्षात्कार का जो पत्र होगा, इण्टरव्यू-लेटर, वही रेल में टिकट के रूप में माना जायगा या बस के भाड़े के लिए वह टिकिट माना जाएगा ? हरियाणा सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की है । क्या सारे देश में यह साक्षात्कार पत्र लेकर अगर कोई जाय तो उसको रेल-टिकिट या बस-टिकिट मानकर साक्षात्कार के स्थान तक जाने और आने की व्यवस्था होगी ?

महोदय, दो उप प्रश्न हैं, एक-एक वाक्य में ही पूछूंगा । लोक सेवा आयोग की जो आयु-मर्यादा है, इस आयु-मर्यादा के कारण ग्रामीण अंचलों में रहने वाले और पिछड़ी जातियों के लोगों को अवसर नहीं मिलता है । इसको देखते हुए क्या इस आयु-मर्यादा को बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? दूसरा, एम्पलायमेंट एक्सचेंज में जो सूची बेरोजगारों की बनाई गई है, क्या वह सूची सार्वजनिक घोषित की जाएगी, पब्लिक की जाएगी ताकि कोई भी बेरोजगार जाकर वहां अपना नाम किस क्रमांक पर था देख सके और आने पहले और बाद में अगर किसी को नौकरी मिली हो, तो उसकी शिकायत करने का उसे अवसर मिल सके ?

इन प्रश्नों का उत्तर मंत्री जी दें, यही मैं प्रार्थना करता हूं । अंत में मुझे कहना है, एक युवा प्रधानमंत्री हमारे हैं, 60 फीसदी युवाओं का यह देश है, इसको देखते हुए सरकार को क्या कभी लगता है कि इस देश में एक पूर्ण रोजगार की स्थिति आएगी ? अगर लगता है तो वह कब आएगी ? यह बताने का कष्ट करें । धन्यवाद ।

SHRI V. NARAYANASAMY: Mr. Vice-Chairman, Sir the hon. Minister was pleased to answer the question relating to the unemployed youths in the country estimating them as 30 million as per the figures available with them. Sir, in our country, there are more than 3,000 urban and semi-urban areas. In that only in 200 cities alone, 70 per cent of the rural labour force has migrated and work there either as rickshaw pullers or in the houses of rich people or as watchmen. But Sir, I have gone through the Plan document relating to labour and manpower planning. I find that the thrust given for manpower planning and for creation of employment for the rural and urban sector is not

[Shri V. Narayanasamy]

enough. I was not satisfied with the ex planation given in the document. Sir, it is an admitted fact that in the year 1985, tho unemployed force was only 26 million and within a period of one year, that is by 1986, it rose up to 30 million. This four million figures within a period of one year which was not available in the earlier period as per the survey conducted is the increase. Sir, I would like to know from the hon. Minister whether the survey conducted or the registers maintained in the employment exchanges are not correct or those persons who are employed have not cancelled their entry in the employ ment exchanges or double entries have been made in various employment ex changes by the same person. Apart from that the employment exchanges and the Labour Ministry, are giving training for the entrepreneurs and also for skilled and semi-skilled labour. They think that their job is over with that. Sir, I welcome the introduction of com puters in the employment exchanges. They would like to check the double entry or even the manipulation in the records. I welcome it. Sir. I put a question about a week ago as to how many unemployed doctors are there in our country: it is an alarming figure of 3500 at present. Apart from those who have gone abroad, those doctors who are unemployed in our country are 3500. Sir, I quite agree with the hon. Minister that it is not his sole job. The hon. Minister may say that. But I would like to know what is the total amount of money spent by the Government for each doctor. Is the capa city being unutilised and the doctors who are capable of treating patients are not able to get employment? Let us come to the lower category. Tn the employment jxchanges, the names are entered. A per-on who has studied up to 8th standard and above is a person who is blessed with he Labour Department and with the mployment exchange. When he passes SC, he does not get any interview. Te does not get employment for the ost of a watchman or even peon or any ther fourth class category. He is a curse, lenever the person approaches the emp-yment exchange, they say, "You have passed SSLC. You will not get the interview card." I personally know of cases where they have not got even a single employment opportunity in spite of being registered for ten years and more. Therefore, I would like to know from the hon. Minister what the fate of those persons who have passed SSLC, B.Sc, BA., M.A. M.Sc etc. is. What is the Ministry going to do for them?

Sir, another alarming thing is the rural unemployment. It is a known fact that the Government is bringing very good proposals in the NREP, RLEGP and other programme for the rural poor to get employment. But it is not catering to the needs of even five per cent of the people living in rural areas. In the matter of training programmes, the Labour Department is concentrating on the urban limits and not on the rural areas. Employment exchanges are functioning as unemployment exchanges. The person who has registered himself curses the employment exchange. He does not go there because he does not like it. That is the practical position today. It is good that the new education policy which is linked to job has come. But it will take fifteen years to achieve the objectives of that policy. What are you going to do during these fifteen years?

Here, I would like to refer to certain figures reported by the Confederation of Engineering Industry about the industrial sector alone. In the industrial sector, during the Seventh Plan period, against an overall growth rate of eight per cent, the engineering industry is slated to grow at 10.2 pe rcent per annum. From 1974-75 to 1981-82, the industry's value of output has registered an annual compound growth rate of 16.8 per cent, invested capital 12.9 per cent, and value addition. 12.8 per cent. However, employment has gone up only by 3.8 per cent in the industrial (tector,

Sir, the investment has gone up. The production has gone up. But the employment growth is not there. If you go through the Plan document, you find thrust

only for the labour force, man-power planning. But what happens here is contrary to that. The industrial sector is not absorbing the man-power which is required by it. When the investment is more, when the production is there, automatically, Sir, man-power should he more. The persons employed should be more. But it is not there. It is not proportionately increasing. On the other hand, it is decreasing. Why is it so? Has the Ministry concerned found out the reason for it?

Now, 1 shall refer to some figures given by the International Labour Organization. It says that the percentage of youth uemployment in the developing countries ranges from 27 to 73 per cent. Jn the developed countries it has gone up from 22 to 30 per cent. Sir. the youth population is so much that in the age group of 15 to 24 years, it increases from 755 million in 1985 to 1.17 billion in 2005. This is the world figure. But unemployment is on the increase in the developing countries. If it is so in the developed countries, we can agree. But in the developing countries it has gone up from 23 to 75 per cent. What is the Labour Ministry doing about it?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRl H HANUMANTHAPPA): Please, conclude now.

SHRI V. NARAYANASAMY; I will put only one question. I will conclude within three minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRl H. HANUMANTHAPPA): Within one minute, please. Put the question.

SHRI V. NARAYANASAMY: For puting the question, I will have to give certain figures. By that, I will be helping the Minister also. The Minister will escape with the plan document. Therefore, I am giving the other figures also In the developing countries automatically whateevr be the technological development or the scientific research that is going on, when manpower is reduced, it will not be reduced to the extent of 50 per cent it may be reduced to about 5 fo 10 per cent. But in our country we find that employment ratio from year to year is not more than 4 per cent. If this average continues, the unemployment problem cannot be solved by our Government. The thrust should be on the agricultural sector. The Minister said, '1 welcome it". Agricultural workers in the unorganised sector are about 27 million. He is bringing a legislation for them. I welcome it. I shall show these figures also to the Minister: these are not correct figures. I know personally, when we visited rural areas we found young and energetic youth unemployed. Whether educated or uneducated, what is your plan for the purpose of employing those persons? Seventy per cent of population in rural areas is unemployed. They ar© migrating to towns and cities in search of employment there. Therefore, what is your plan for employing rural youth? What is your plan for employing educated youth in urban and rural areas? Giving training alone will not solve the problem It may be solved only to the extent of just 4 to 5 per cent, not the entire problem. The public sector is employing more persons, the Governments are employing more persons: technical category people are getting employed. The New Education Policy has come into operation only a year back. Under the old Education Policy lakhs and lakhs of graduates, undergraduates, post-graduates, are unemployed. This an alarming situation. Government of India is not providing them jobs. I quite agree that they cannot provide jobs to all: they can give only to a limited extent. What about public sector undertakings? What about private industries? You are giving *p* lot of money to them by way of so many concessions. What are they doing? Are they employing enough people? Merit is considered not always in the private industries also. Persons are employed according to the whims and fancies of the employers. Therefore I urge upon the Government to consider this question seriously. A son or a daughter who has been educated in a family up to BA or BSc or MA or MSc is a burden on that family if he or she is not employed. This is what I want to drive horn* to the honourable Minister. Of course, I understand that it is not his sole responsibility. But still Government must make an effort and in order to reduce the burden of the family on account of its

(Shri V. Narayanasamy)

unemployed grown-up children, unemployment dole should be given as is being given in other countries, to the educated unemployed. They are giving vocational training, they are conducting diploma courses. But what is the percentage they are covering? What is the percentage of youth they are covering? *(Time-bell-rings)*

I have put three or four questions; (1) About unemployment dole: (2) Why is there such an alarming unemployment situation? In 1986 it was 26 million: now it is 30 million; that is, in one year it has increased by 4 million. (3) What is your plan for rural sector and urban sector for employing at least 75 per cent of the unemployed population in the country?

7.00 P.M.

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY (Andhra Pradesh): Sir, every freedom fighter, everybody who fought for the freedom of our country, including myself, though that man would be the centre of the stage for development. But, unfortunately, after Independence, certain forces emerged and there was only accumulation of money and there was monopolisation. Against Directive Principles of State Policy there has been accumulation of wealth and because of the accumulation of wealth, though at first it was said that ours would be a mixed economy, we are living under conditions of capitalist economy, pure and simple, with all the contradictions of capitalism coming into force. And, Sir, unemployment is going to consume the very Government which is ruling this country for the past forty years. My friends have stated the magnitude of the problem. Now, how are you going to solve it? The agricultural sector has to pay for industrial development. The agricultural sector has become impoverished. The peasants have become poorer. Feudal economy is still persisting, discrimination is there and untouchability is there. People are running to the towns and cities. As my other friends have pointed out, because there is uneven development and because there is concentration of wealth, even though there are three thousand urban centres, only two hundred centres arc having this concentration of labour population coming from the villages. There is the growth of the slums also. More than fifty to sixty per cent of the population in all the big cities is dwelling in slums. This is the picture. How are you going to solve, all these problems? Any statistics we take will indicate that there are about thirty million registered unemployed people. But registration does not give tho complete picture. Millions seeking employment do not go to the Employment Exchanges. It en only be an indicator of the skilled and unskilled labour available in the country. You thought that with your Plans and with the 5.5 per ceat growth rate, you would be able to giva full employment. But your hopes have been belied. While you are able to give employment to 4.2 per cent, unemployment is growine at the rate of 14 per cent. You canot catch up with it. That is why, after every Plan, you have got more and more backlog which is reflected in these huge figures.

Now, what about the industrial climate? What about the agricultural sector? The cottage industries have been destroyed and the village economy has broken down. The villagers do not have any purchasing power at all and there is remunerative price for what they produce. There is the ghastly picture of 1.40,000 industrial units remaining sick. You are thinking that your problem is only to get rid of the sick industries. After all, this is because of your mismanagement and, therefore, you cannot easily revive them also.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRl H. HANUMANTHAPPA); You do not have any questions to ask?

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: I can ask any number of questions I am of the opinion that unless structural changes are brought about in the society, you cannot even touch the fringe of the problem. Unless the system of exploitation is destroyed in the country, nothing can be done. You know, in the other House, Bhaeat Sinsh threw a bomb for the deaf to hear. Unless you sive land to the tiller, unless vou end the monopolies, unless you nationalise the multinationals?

companies, unless you nationalise the MRTP companies, unless you nationalise all the agro-industries, unless you decentralise, you cannot think of solving any of the problems facing the country. Decentralise the entire set-up. Then see to it that our villages nourish, that unequal trade is removed and the peasant gets remunerative price. *(Time Bell rings)* You have to do ail these things, My dear sir, *I* am sorry that this Government cannot do all these things. That is why I sympathise with the plight of the Labour Minister who has been given a budget of Rs. 18 crores last year. He was not able to spend that even. We have so many problems. Child labour is a problem, youth employment is also a problem and everything is a problem. So where is Rs. 18 crores? It is not even a drop.

Finally, when you cannot tackle problems, better sleep over problems. That is what the Government is doing. I have to point out that, true but strange, in the entire Plan document of 1985—90 one does not come across any estimate of unemployment at the end of the Seventh Five Year Plan. How can you come to an estimate? You cannot.

There is drought. There are floods, you are not able to implement the Plan. Thousands of problems are there and the economy itself is in doldrums. All your schemes of self-employment are flops. You may have 'melas' here and there, but these 'melas' are not going to put people on their feet unless you re-structure the entire economy of the country. *(Time Bell rings')*

Therefore, Sir, I want to state emphatically that you launch yourself on building up socialism, let those people who are the watch-dogs of imperialism and of monopoly capitalism be prevented from public life, and let real, true nationalism assert itself; let us go forward to build a socialist economy in which all these problems can be solved. Thank you.

श्रीमती वीणा वर्मा : (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, भारत का संविधान एक प्रतिष्ठित दस्तावेज है। विश्व के अच्छे संविधानों में उसकी गणना होती है। पिछले 37 सालों के अनुभव से सिद्ध हो जाता है कि भारतीय संविधान में आधुनिक युग की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याओं से जूझने और उनका समाधान निकालने की क्षमता है। लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट है कि संविधान की व्यवस्थाओं को जब तक क्रियान्वित नहीं किया जाता तब तक उनका कोई लाभ नहीं है। साथ ही यह भी कि गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, जातिवाद, सांप्रदायिकता तथा क्षेत्रवाद जैसी आर्थिक व सामाजिक बीमारियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए संविधान से प्रेरणा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। यह किसे मालूम नहीं कि आजादी के 40 सालों बाद भी भारत में युवक बेरोजगारों की संख्या करोड़ों में है। आजादी के बाद देश में जो युवा पीढ़ी आई है उसके सामने सबसे बड़ा संकट उसके अस्तित्व का है। यह अस्तित्व का संकट उसकी बेरोजगारी से जुड़ा है। यानी उसके पास आज ओसत जिन्दगी जीने के लिए साधन नहीं हैं। वह कुल मिलाकर व्यवस्था और नियति के आगे झुका हुआ जिन्दगी का एक विवश कथानक बन चुका है जिसकी कोई नहीं सुनता न परिवार, न समाज, और न देश। उसके चारों तरफ अंधकार का काला साया मुंह बाये खड़ा है, जहां से प्रकाश की जरा भी आस्था नहीं झांक रही है।

यूं तो बेरोजगारी की समस्या विश्व-व्यापी है किन्तु जिस तरह हमारे देश में है और जगह इतनी नहीं। खासतौर से शिक्षित बेरोजगार की जो हालत अपने देश में है उतनी कहीं नहीं। हालात यह है कि साहित्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्र में ऊंची डिग्रियां प्राप्त करने के बावजूद भी अपने देश में युवा वर्ग को कहीं कोई जीविका नहीं है। इस तरह से डिग्रियां युवकों के लिए या तो बोझ बन

[श्रीमती वीणा वर्मा]

गई हैं या डस्ट बिन की खुराक । एक प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक ने कहा था, "आज अपने देश में जिस युवक के पास जितनी बड़ी डिग्री है वह उतना ही बड़ा बेरोजगार है ।" आजादी के इन चालीस वर्षों में भी सरकार तमाम प्रयत्नों के बावजूद बेरोजगारों की बढ़ती फौज पर काबू नहीं कर सकी है । फलतः आज शिक्षित युवकों में 70 प्रतिशत लोग या तो जीवन से निरर्थक हो गये हैं या फिर परिवार व समाज के लिये बोझ बन गये हैं ।

अतः मेरा पहला प्रश्न यह है कि हमारी सरकार इस भयानक समस्या से पूरी तरह बेखबर न भी हो तो इतना तो सच है कि अभी तक इस दिशा में सार्थक कदम नहीं उठाये गये हैं । पिछले वर्षों में शिक्षित बेरोजगारों के लिये जो योजनायें बनाई गई हैं उनकी आज पड़ताल करने की जरूरत है कि वे कितनी कारगर सिद्ध हुई हैं, क्या मंत्री जी इस प्रश्न का जवाब देंगे कि इस प्रयास में वे अपनी योजनाओं के माध्यम से कितने सफल हो पाये हैं ?

मई दिवस 1987 की घोषणा के अनुसार इस समय देश में रजिस्टर्ड-शुदा बेरोजगारों की संख्या 3 करोड़ तक पहुंच गई है । अब आप अंदाजा ला सकते हैं कि पिछले दशक से लेकर अब तक बेरोजगारी की रफ्तार किस कदर बढ़ी है । मेरे ख्याल में देश में बेरोजगारी इतनी ही नहीं बल्कि इससे ज्यादा है । वैसे हमारी सरकार और पुरुष प्रधान समाज बेरोजगार सिर्फ पुरुषों को ही मानता है स्त्रियों को नहीं । जबकि वास्तविकता यह है कि आज पुरुष और स्त्री समान स्तर पर बेरोजगार हैं । आखिर यह शिक्षा की जब कल्पना संभव है तो बेरोजगारों की लिस्ट में औरतों को क्यों छोड़ दिया जाता है ? इस वास्तविकता पर भी आज विचार करने की जरूरत है । फिलहाल जो सरकारी नौकरियां हैं उन्हें प्राप्त करने के लिये एक भयानक होड़ लगी हुई है इस होड़ में भी वे लोग सफलता हासिल कर लेते हैं जिनके पास ब्यूरोक्रेसी तक पहुंचने के लिये जेक है । विभिन्न राज्यों में लोक सेवा आयोगों की स्थिति लगभग यही है। खासतौर से मैं बिहार का उल्लेख करना यहां उचित समझती हू । प्राप्त सूचनाओं के मुताबिक बिहार लोक सेवा आयोग में रिक्तियां साल दर साल कम भरी जा रही है । पदों को खाली रखकर नियुक्तियां नहीं करने का यह गणित आखिर बेरोजगारी की विकराल समस्या का किस प्रकार समाधान कर पायेगा ? बिहार लोक सेवा आयोग में आज न केवल प्रान्तीयता का बोलबाला है बल्कि यह कहना चाहिए कि अभ्यार्थी की योग्यता को दूसरे, तीसरे दर्जे की चीज मानकर पदों की नियुक्तियों में सिर्फ सिफारिश को मैरिट मान लिया गया है । पिछले वर्षों में बिहार लोक सेवा आयोग में व्याप्त अनियमितताएं और भ्रष्टाचार की खबरों से इसी तथ्य की पुष्टि है । उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थिति बेहतर जरूर है पर वहां पदों की नियुक्तियों में दो-दो साल का समय लिया जा रहा है । अभी तक 1986 में ली गई राज्य सेवा की परीक्षाओं का रिजल्ट नहीं निकला है । यह स्थिति हमारी नौकरशाही के लिये चिन्तनीय भले ही न हो किन्तु उन बेरोजगारों के लिये काफी कठिन है जो फीस और किताब के लिये कर्जे मांगकर प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में अपनी आजमाइश कर रहे हैं । फिलहाल बेरोजगारी की जो भयानक स्थिति है उससे निपटने के लिये कुछ प्रश्न और कुछ सुझाव मेरे इस प्रकार से हैं ।

1. नयी शिक्षा नीति को पूरे देश में तुरन्त लागू करना चाहिए ताकि नयी

दिशा नीति का लाभ आने वाली पीढ़ी को मिल सके।

2. उच्च शिक्षित बेरोजगारों को उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षा बेरोजगार योजना के तहत भत्ता कब तक दिया जायेगा ?

3. क्या शिक्षित बेरोजगारों में युवकों के साथ युवतियों को भी जोड़ा जायेगा ? यदि हां, तो उन्हें कब तक जोड़े जाने की संभावना है ताकि उन्हें भी बेरोजगारी का भत्ता मिल सके।

4. क्या केन्द्र सरकार सभी राज्य सरकारों को आदेश देगी कि जल्दी से जल्दी उनके यहां जो रिक्त स्थान उनको भरा जाय ?

5. मैं मंत्री महोदय से यह भी पूछना चाहूंगी कि बेरोजगारी की समस्या के संदर्भ में शिक्षित बेरोजगारों की बढ़ती फौज से वे कैसे निपटेंगे ?

श्री राम अवधेश सिंह : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपको और जिस माननीय सदस्य के प्रयास से आधे घंटे की यह बहस सदन में आई है, उनको और माननीय सभापति जी का धन्यवाद करता हूं जो मुल्क के सबसे बड़े जलते हुए सवाल को सदन में चर्चा के लिये लाया गया है।

महोदय, मैं सब से पहले आप से अर्ज करना चाहता हूं। बात शुरू करने के पहले कि इस में पक्ष और विपक्ष एक हैं और इसमें कोई ज्यादा तनाव नहीं है। आपसे मेरा निवेदन है कि थोड़ा उदार रहूं क्योंकि पिछले दिनों हम 9 बजे तक भी बहस करते रहे हैं। यह मेरी निश्चित राय है भारत की स्थिति देखते हुए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सामंतवादी राज व्यवस्था और कट्टर पंथी समाज-व्यवस्था की क से निकली हुई यह राक्षसी संतान बेरोजगारी है। आप नहीं कह सकते कि इस बेरोजगारी का कोई एक खास कारण है या कोई एक नीति की विफलता की वजह से यह है या नीति के कार्यान्वियन न होने के कारण से बेरोजगारी है और देश की यह हालत है। इसके कई कारण है जैसे मैंने तीन मुख्य कारण शुरू में बताए हैं पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था, सामंतवादी राजव्यवस्था, कट्टर-पंथी जिसको हम कहते हैं ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था। मैं ब्राह्मण जाति के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में फर्क करियेगा क्योंकि जो विचाराधारा दबे हुए कुचले हुए लोगों को समाज में उचित सम्मान नहीं देना चाहे और बिना कमाए हुए आराम करना चाहे भोगना चाहे उसको हम कहते हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था। माननीय मंत्री पांजा साहब ने जो जवाब दिया उसको देख कर मुझे जितना गुस्सा आया उतना गुस्सा पहले कभी भी नहीं आया क्योंकि मैं जानता नहीं उन्होंने जो जवाब दिया किसी अफसर ने बताया होगा मैं उसको पढ़ कर कोट कर देना चाहता हूं—

"During the 7th Plan period it is expected that employment will grow at the rate of 4 per cent per year as compared to the expected growth rate of 2.46 per cent per year in the labour force. Over the Plan period, the employment potential is expected to rise by 40 million standard persons."

यह दूसरी किताब है जिसमें इसी से मिलती जुलती बात है मैं एक लाइन पढ़ना चाहता हूं —

"It has also been estimated that the backlog of unemployment at the outset of the 7th Plan was of the order of 92 lakh. The net addition to the labour force in this age group is expected to be 393.8 lakh and the additional employment generation to be of tho order of 403.6 lakh standard person years during the 7th Plan."

मतलब यह है कि 10 लाख ज्यादा काम हमारे पास रहेगा जितने लोग रहेंगे। क्या मतलब हुआ ? यह तो इस्टीमेशन है और

[श्री राम अवधेश सिंह] :

यह किताब में लिखा गया है। यह हाउस में बताया गया है। यह उसी तरह से बताया गया है एव्रज निकाल कर ग्रोथ रेट और इम्पलायमेंट अपर्चुनिटीज के बारे में जिस तरह से मुझे एक किस्सा याद आता है। हम लोगों के देहात में चलता है। एक पंडित जी थे, एक नदी पार करनी थी तो उसका एवरेज निकाल लिया... (समय की घंटी) कहीं दो फीट, कहीं पांच फीट, कहीं 10 फीट, और एवरेज निकाल लिया कि एवरेज है साढ़े तीन फीट। लड़का था चार फीट का तो कहा कि पार कर जायेगा। "लेखा जोखा थाहे, लड़का डूबा जाये काह।" लेखा जोखा यानी हिसाब लगता है कि साढ़े तीन फीट है तो कैसे डूब गया। उस बेवकूफ को मालूम नहीं था कि बीच में पानी दस फीट है एक जगह, कवल एवरेज निकालता था। अतः इस तरह से जो आंकड़े निकालते हैं ये लोग सरकार का दिवाला निकालते हैं, देश का दिवाला निकालते हैं और ऐसे ही लोग देश की इज्जत को डुबोते हैं। एसे ही इनको अफसरों ने बता दिया कि दो दिन में लंका पर विजय प्राप्त कर ली जायेगी, दो दिन में सफाया हो जायेगा...

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : कहां से कहां जा रहे हैं।

श्री राम अवधेश सिंह : इस तरह से हम वहां फंस गये हैं, किस तरह से हमारी नाक काट रही है यह आपको भी पता चल रहा है, हमको भी पता चल रहा है, हम लोग शर्म से झुक रहे हैं। इसी तरह के ये आंकड़े हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि श्री लंका आपके सिर पर चढ़ गया है। श्रीलंका में हमारा तीन करोड़ रुपया रोज खर्च हो रहा है, चार डिवीजन फोर्स हमारी लगी हुई है। आप क्या बात कर रहे हैं। आप लोग हस्तक्षेप मत करें मैं दूसरी बात कर रहा हूं। इसी बात पर मुझे टाइम लगाने दीजिये, उधर मत ले जाइये। मैं यह कहना चाहता हूं कि ये आंकड़े सही नहीं बताये जा रहे हैं और गलत आंकड़ों पर प्लानिंग कमीशन के जरिये, लेबर विभाग के जरिये और फाइनेंस विभाग के जरिये ये सारे काम किये जा रहे हैं, बनाये जा रहे हैं। इनका नतीजा उल्टा निकल रहा है महोदय, आपको भी महसूस होगा कि अभी 4 पदों के लिये निकाल दीजिये तो कितनी एप्लीकेशंस आती हैं बी० एज० की आपको पता चल जायेगा कि ये जो आंकड़े दिये जा रहे हैं कि इतने लोग बेरोजगार हैं ये बिल्कुल गलत हैं और उस आधार पर हम नहीं कह सकते हैं। मेरे अपने आंकड़े हैं कि प्रति परिवार एवरेज एक आदमी निश्चित तौर पर बेरोजगार है। मोटा आंकड़ा है। सारे प्लानिंग कमीशन का आंकड़ा एक ओर रख दीजिये लेकिन एवरेज प्रति परिवार औसतन एक आदमी जरूर बेरोजगार है। हमारे देश में साढ़े 11 करोड़ परिवार हैं तो साढ़े 11 करोड़ लोग तो निश्चित रूप से बेरोजगार हैं। किसी परिवार में दो हैं, किसी में तीन हैं, किसी में एक भी नहीं लेकिन एवरेज एक जरूर है। तो साढ़े 11 करोड़ कम से कम बेरोजगार हैं, इससे कम नहीं हैं। जो इससे कम कहते हैं वे केवल झूठे आंकड़े आपको देते हैं देश को गुमराह करते हैं... (समय की घंटी)...

महोदय, जो हमारी उद्योग नीति है उस पर में कहना चाहता हूं। जो नीति हमारे प्रथम प्रधान मंत्री जी ने...

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : राम अवधेश जी घड़ी के साथ चलिये। आपका जो टाइम था उसका डबुल मैंने दे दिया, आपकी विनती के अनुसार अब और भी आग जा रहे हैं आप।

श्री राम अवधेश सिंह : ... (व्यवधान) मैं आप की मदद कर रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : मेरी भी मदद कीजिए।

श्री राम अवधेश सिंह : उस उद्योग नीति का पालन किया गया रहता... (व्यवधान) मैं कुछ नीतियों की कमजोरी की वजह से बेरोजगारी रूपी फैले हुए राक्षस को दबाने के लिये कह रहा हूं। आपसे उन नीतियों की कमजोरी के बारे में निवेदन करूंगा। जो उद्योग नीति हमने स्थापित की थी। 1956 में अगर उसका भी पालन किया गया

रहता तो निश्चित तौर पर हम कुछ कारगर हुए रहते और जो आर्थिक विषमता इस देश में फैल रही है वह कम हुई रहती, बेरोजगारी कम हुई रहती और परचेसिंग पावर, जो क्रय शक्ति है जनता की, जो घटती जा रही है गांवों में, वह क्रय शक्ति भी बढ़ती । 1956 की उद्योग नीति क्या थी ? बसिक की एण्ड हैवी इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर में लगायी जायेंगी । निश्चित तौर से उसमें कसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं होगा । और मीडियम साइज्ड इंडस्ट्रीज ज्वाइंट सैक्टर में हों और कंज्यूमर गुड्स जो दैनिक उपभोग की चीजें हैं, जैसे बाल्टी है, लौटा है, कुर्ता है, लुंगी है, गमछा है, कुदाल, फाल, तेल, जूता, आदि, यह सारी चीजें लघु उद्योग में और काटेज इंडस्ट्रीज में लगाने की बात थी उद्योग नीति में, लेकिन उस उद्योग नीति को हमने माना नहीं ।

हमारे माननीय सदस्य महाजन जी ने इस ओर इशारा किया कि सिर से पैर तक टाटा और बाटा में हम फंस गये, जो पैसा हमारे गांव में जाना चाहिए था, गांव का पैसा गांव में रखना चाहिए था, गांव का पैसा हम लोग भोजपुरी में कहते हैं—"गांव का पैसा गांव में छेको" तो गांव का पैसा गांव में छेके होते, घेरे होते, तो स्थिति दूसरी होती । आज गांव का पैसा टाटा, बिरला सिंहानिया, ब्रिटानिया, टनटनियां और झुनझुनियां जितने हैं उद्योगपति, इनका कराड़ा गांव-गांव में, घर-घर पहुंच गया है, वहां से पैसा निकल कर चला जाता है कानपुर, अहमदाबाद, शोलापुर, बम्बई और कलकत्ता । यह पैसा हम लोगों ने गांव में रखा नहीं, जनता की परचेजिंग शक्ति खत्म हो गई है । गांव की जब तक परचेजिंग शक्ति आप बढ़ायेंगे नहीं, तो कोई उद्योग-धंधे या बड़ा कारखाना भी नहीं फैला सकते । बड़े कारखाने में भी चाहे अगर क्रय-शक्ति जनता की बढ़ेगी, तो बाजार में उसकी मांग बढ़ेगी और वह बढ़ेगी तो इन उद्योगों में भी इम्पलायमेंट अपरचुनिटीज क्रियेट होंगी । जहां तक शिक्षा नीति का सवाल है ....

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) नहीं, नहीं आप शिक्षा नीति, उद्यो नीति को यहां डिसकस नहीं कीजिए ।

श्री राम अवधेश सिंह : जरा बात तो करने दीजिए ।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : आप सब से ज्यादा टाईम ले रहे हैं । आप कितना बोलेंगे ?

श्री राम अवधेश सिंह : मैं सब से महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं ... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : अगर आप खत्म नहीं करेंगे, तो मैं दूसरे वक्ता को बुलाता हूं ।

श्री राम अवधेश सिंह : यह कोई बात नहीं हुई । इतने में तो मैं एक-दो बात कह दिये होता ।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : अच्छा, जल्दी कह दीजिए ।

श्री राम अवधेश सिंह : महोदय, मूल कारण यहां की दाम नीति है । दाम नीति के चलते यह सारा शोषण हो रहा है और बेरोजगारी बढ़ रही है । दाम नीति क्या है ? अभी क्योंकि खुला बाजार पूंजीपतियों के हाथ में है और जो कुछ दाम तय करने की चीजें हैं, वह सरकारी सैक्टर की जो उत्पादित होती हैं, वह सरकार के अंडर है । तो जैसे मैंने कहा, बेसिक, हैवी और की-इंडस्ट्रीज—तो उसमें की-प्रोडक्ट पैदा होता है, स्टील पैदा होता है, कोयला, पेट्रोल—तो जब इनकी कीमत बढ़ जाएगी, तो सारी चीजों की कीमत बढ़ जाएगी । **(समय की घंटी)**

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : श्री रत्नाकर पाण्डेय । हमें तो हाऊस चलाना है । If you ignore the bell, if you ignore the directions of the Chair, this indiscipline cannot go on like this. Please sit down. I have already called the next speaker. I gave you sufficient tune. Don't argue with me.

श्री राम अवधेश सिंह : आर्गुमेंट तो आप कम ही करते हैं। एक मिनट हमको बोलने दीजिए। क्षेत्रीय विषमता के बारे में एक लाइन बोलकर मैं खत्म करना चाहता हूं। महोदय, यह गरीबी और बेरोजगारी का एक कारण यह भी है कि जहां नेचुरल दौलत पैदा होती है, हमारे यहां 40 फीसदी बिहार में मिनरल रेसोर्सेज हैं सारे देश के, मगर वहां बेरोजगारी सब से ज्यादा है, क्यों ?

वह इसलिए है कि केन्द्रीय सरकार ऐसी नीति चलाती है कि जो लोहा, जो कोयला बिहार में पैदा होता है, जिस कीमत पर वहां बिकता है, उसी कीमत पर वह पंजाब में, उसी पर बम्बई में और उसी कीमत पर गुजरात में सरकार पहुंचाती है। जब उसी कीमत पर कोयला, लोहा, मैंगनीज वह वहां पहुंचा देगी, तो फिर बिहार में कोई कारखाना क्यों लगायेगा। बिहार में तो बेरोजगारी बढ़ेगी ही।

तो इसी ढंग से, क्षेत्रीय विषमता के जरिए भी बेरोजगारी फैलती है। मेरी सरकार से मांग है कि बिहार के साथ न्याय किया जाए। अगर बिहार के साथ न्याय नहीं किया गया तो मैं इस सदन के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं....

उपसभाध्यक्ष श्री (हेच० हनुमनतप्पा): अब बंद कीजिए।

श्री राम अवधेश सिंह : कि हम लोग कोयला आना बंद कर देंगे, सत्याग्रह करेंगे और रेल चलना बंद करेंगे। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : डा० रत्नाकर पाण्डेय।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : उपसभाध्यक्ष जी, दिनांक 24 नवम्बर, 1987 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 244 में युवकों में बेरोजगारी के संबंध में जो प्रश्न था और सरकार की ओर से जो उत्तर आया था उस पर माननीय संसद सदस्य श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव ने आधे घंटे की बहस की मांग की थी और उस बहस के अंतिम वक्ता के रूप में मैं कहना चाहूंगा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के अनुसार मार्च, 1985 में 92 लाख व्यक्ति युवा आयु वर्ग के बेरोजगार थ और सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में कम होंगें। लेकिन उसी दिन स्थानापन्न लेबर मिनिस्टर श्री अजीत पांजा ने जो और विस्तार से उत्तर दिया था माननीय सदस्यों की जिज्ञासा के अनुसार, उसमें अप्रेल, 1986 का डाटा दिया था उसमें 3 करोड 3 लाख 61 हजार नौजवान बेकार हैं। यह इस बात को शो करता है कि बेरोजगारी की संख्या जिस प्रतिशत से बढ़ी है वह चिन्ता की बात है, सरकारी आंकडे जो दिए गए हैं वे परेशानी बढ़ाते हैं। मान्यवर, यह बहुत बड़ा देश है और यहां सब को संविधान के अनुसार अपनी योग्यता के अनुरूप, अपनी शिक्षा, अपनी कार्य-कुशलता, अपने स्किल और प्रतिभा के अनुसार काम करने का बराबर का मौका दिया जाना चाहिए, परन्तु देखा यह जाता है कि रोजगार कार्यालयों और चाहे कोई और माध्यम सेवा की हो उसमें न्याय नहीं हो पाता है। उसमें सोर्स चलते हैं, रोजगार कार्यालयों से भी वही नाम पहले नौकरी के लिए भेजे जाते हैं जिन पर बड़ी सिफारिशें होती हैं। इस देश में एक नया काम शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है। 1827 में मैकाले ने जो शिक्षा पद्धति स्थापित की थी और क्लर्क बनाने का कारखाना पैदा किया था और उसी पद्धति पर सैकडो वर्ष से हम चले आ रहे थे परतंत्रता के युग में और स्वतंत्रता के 40वें वर्ष में हमने जाब-ओरिएंटेड शिक्षा पर जोर दिया है। इस पर अगर हम विशेष ध्यान देंगे तो कोई बढ़ई का काम करता है, अच्छा शिल्पकार है, अच्छा भवन निर्माता है, अच्छे जूते बनाता है, अच्छी बुनाई का कार्य करता है तो उसे कोई डिग्री की जरूरत नहीं, अपनी योग्यता के अनुसार उसे काम मिलेगा इस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं

होती हैं संघ लोक सेवा आयोग की, चाहे, केन्द्रीय सरकार की हों या प्रान्तीय सरकारों की हों उनमें हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने साजिश कर रखी है अंग्रेजी को अनिवार्य रूप से परीक्षा के प्रश्न पत्रों के उत्तर का माध्यम बनाकर और आज जो 40 वर्ष बाद एक बहुत बड़ा लाभ इस क्षेत्र में देश को हुआ है जो छात्र पढ़ते हैं वे अंग्रेजी अशुद्ध बोलते हैं, अशुद्ध पढ़ते वे लिखते हैं और अशुद्ध उच्चारण करते हैं तथा ब्यूरोक्रेट्स जो हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के वे अंग्रेजी को अनिवार्य बनाए रखना चाहते हैं । ऐसी स्थिति में सरकारी सेवाओं के लिए जब तक हम भारतीय भाषाओं को, क्षेत्रीय भाषाओं को और हिन्दी को अनिवार्य नहीं करेंगे तब तक जो हमारा जनतंत्र का समानता का सिद्धांत है कि अपनी योग्यता के अनुरूप लोगों को काम मिलेगा और अपनी मातृभाषा में अपने भाव प्रकट कर पायेंगे, उस अनुरूप लोगों को काम नहीं मिलेगा। माननीय उप सभाध्यक्ष जी, मैं बनारस का रहने वाला हूं जो उत्तर प्रदेश में सब से अधिक फारेन एक्सचेंज देता है गलीचा व्यवसाय के माध्यम से और वहां हमने प्रस्ताव पास कर लिया कि बाल मजदूरों का शोषण नहीं होगा । छोटे छोटे बच्चे जो गलीचा बनाते हैं उनके-लिए बहुत से उद्योगपति मेरे पास आये कि साहब उसको बाल मजदूर समाप्ति प्रथा पर छूट दिलवा दीजिए । मैंने कहा कि मैं कतई छूट नहीं दिलवाऊंगा और मैं इसके विरुद्ध हूं कि लेबर के नाम पर बच्चों का शोषण किया जाए। होता यह है कि कहते हैं कि बच्चों की उंगलियां बड़ी मुलायम होती हैं इसलिए वे गलीचा बहुत अच्छा और जल्दी-जल्दी बुनते हैं । तो हमारी सरकार अच्छे-अच्छे काम कर रही है, लेकिन जिस रूप में उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है वह नहीं हो पाता है। हम योजनाएं बनाते हैं, संसद में कानून बनाकर पास करते हैं लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स उन योजनाओं को कार्यान्वित करते हैं उसमें उनके काम करने के तरीकों में सुधार की बहुत जरूरत है । नहीं तो हमारा 92 लाख बेकार युवक तत्काल दो वर्षों में 3,03, 61,000 नहीं हो जाता ।

जहां तक गांव का प्रश्न है, गांव में जो बड़े-बड़े खेतिहर हैं, वह मजदूर के रूप में खेत में काम करने वालों का शोषण करते हैं....(**समय की घंटी**) जब तक हमारा जो सीलिंग एक्ट है, उसके अनुसार उससे अधिक जमीन जिनके पास है, जिन्होंने अपने कुत्तों, बिल्लियों, पशुओं या विभिन्न नामों से जालसाजी करके सारी संपत्ति अपने में एकत्र कर रखी है, जो गांव समाज की जमीन निकलती है, उनका उचित ढंग से वितरण नहीं होता है, तब तक यह बेरोजगारी की समस्या बढ़ती ही जाएगी ।

इसी तरह हमारे देश में जो बड़े-बड़े मिल मालिक हैं, बड़े-बड़े पूंजीपतियों के घराने हैं, उनकी भी संपत्ति का एक निश्चित निर्धारण होना ही चाहिए, अगर समाजवाद इस देश में लाना है, इक्विटी इस देश में लानी है और उन सेठों की, उन बड़े-बड़े मल्टीनेशनलस के जो घराने हैं, उनकी सारी संपत्ति को जब्त करके गरीब बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सकता है, उन्हें उचित ढंग से हिस्सा मिल सकता है ।

जहां तक बेरोजगारों का प्रश्न है, बेरोजगारों को भत्ता मिलना चाहिए । जब तक उन्हें काम नहीं मिलता है, तब तक उनके लिए, जो भारत सरकार ने अनेक योजनाएं बनाई हैं, उसमें बेकारी भत्ता देने का कोई प्रावधान किया है कि नहीं किया, यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं । सर, एक-डेढ़ मिनिट और लूंगा । ...

महोदय, ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री रामानन्द यादव जी ने एक दिन हम लोगों को दावत दी । हर प्रांत के लोगों को बुलाया और उसकी मीटिंग में उनका कागज मैंने देखा, जो सप्लाई किया गया था लिटरेचर, उसमें था कि 33 परसेंट गांव में रहने वाले प्रत्येक गरीबी की रेखा में जिंदा रहने वाले परिवार में एक व्यक्ति को काम देंगे । कागज में तो है, लेकिन मेरे बनारस जिले में ही देखिए, एक भी परिवार को काम नहीं दिया गया है । इसलिए

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

सरकार की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, कागज पर कुछ और प्रेक्टिस में कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं, ईसके लिए सरकार दोषी नहीं है, ब्यूरोक्रेटस दोषी है, जो चीज को नहीं आने देता है। इसलिए जो हमारे ग्रामीण विकास के कार्यक्रम हैं या शहरों में जो विकास के कार्यक्रम हैं, उनको इस तरह से लागू करना है, जिससे जन-जन की आकांक्षाएं पूरी हों, बेरोजगारी मिटे।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं सबसे अंत में मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि बहुत सी जानी संस्थाएँ अरब भेजने के लिए, चीन भेजने के लिए, रूस भेजने के लिए ईरान भेजने के लिए बनाई जाती हैं और उसमें वह लोगों से फीस लेकर मेडिकल के नाम से या दूसरे नाम से गरीबों का शोषण करते हैं। गरीब आदमी नौकरी के लालच में अपने घर के गहने बेचकर उनको देते हैं। न जाने कितनी जाली संस्थाएं इस देश में ऐसी हैं जो विदेश भेजने के नाम पर इस देश के गरीब, नौकरी पाने वाले नवयुवकों का शोषण करती हैं। इनको बेन करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, जिस देश का नवयुवक बेकार होगा, वहां लाख योजनाएं आप बनाएं लाख बड़े-बड़े काम आप कीजिए, लेकिन जब तक उनके आंखों के कोर के आंसू आप नहीं पोंछते हैं उसके और उसके विचारों में उठने वाली आकांक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। हमारे माननीय मित्र चले गए, कह रहे थे ब्राह्मणवाद पर, मैं कहूंगा, भूख ब्राह्मण को भी लगती है, भूख हरिजन को भी लगती है, आवश्यकता कपड़े की सबको होती है, उसको जातियों और वर्गों में न बांटकर हम आवश्यकताओं के अनुरूप बांट कर ही इस देश के बेरोजगार नवयुवकों की समस्याओं का हल कर सकते हैं। जो लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पर सम्प्रदाय के नाम पर, चाहे वह किसी दल के हों इस तरह के विभेद की बातें करते हैं, वे ही सबसे बड़े इस समस्या के लिए दोषी हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जो जिज्ञासाएं मैंने की हैं, उन जिज्ञासाओं की शांति चाहता हूं, उनका वे उत्तर दें। धन्यवाद।

SHRI P. A. SANGMA: Sir, I am grateful to the hon. Members

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA); Who are present.

SHRI P. A. SANGMA: Yes. In fact, I thought I would be required to answer for an hour or so, but I am glad that the issues raised have been common and it would not require much of time to reply.

Sir, unemployment is certainly one of the biggest problems of the country. There is no denying the fact that it is one of the biggest problems and the Government, the Parliament, every responsible citizen of this country is genuinely concerned about this problem. But the Government's policy on employment has been spelt out in the 7th Plan document itself. The Plan document is based on three slogans: of food, work and productivity, and "work" means employment that we have to generate.

There is some confusion about the quantum of unemployment problem. Very often the hon. Members quote the figure of the employment exchanges which have fixed the unemployment figure as 30 million. I have had the occasion to tell this House more than once that as far as Government is concerned, we do not accept the figure of employment exchange as the correct figure. And the reason is this.

SHRI V. NARAYANASAMY: Then why do you get the figure from them when you do not accept it? Why do you quote it in your documents?

SHRI P. A. SANGMA: We do not accept it as the precise figure.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): You just wait. He has not completed his sentence.

SHRI V. NARAYANASAMY: You are disowning your own figures.

SHRI P. A. SANGMA: I am not disowning. I am saying that we do not accept it as the precise and accurate figure because all the unemployed are not registered at the employment exchanges. As the first speaker himself and other friends also, have pointed out, employment exchanges are in the district headquarters. They are in the urban areas. We do not have employment exchange s in the rural areas. Therefore, it will not be correct to say that all the unemployed people are registered in the employment exchanges. It is not so. Therefore, how can we take the employment exchange figures as the correct picture of unemployment?

The second reason is that the employment exchange figures are revised every three years, and within these three years as Mr. Narayanasamy rightly pointed out, there are so many duplications and triplications. There are people who are registered in place 'A' and the same people are registered at place 'B' also because they want to find out jobs in many places. Therefore we do not accept it as the correct figure.

We have made a survey and in that survey it was shown that 27 per cent of the people who are registered with the employment exchanges were already employed and their names were still found in the employment exchange. Seven per cent of the people who are registered in employment exchange were still students. So this is another reason why we do not depend on this figure.

Now the purpose of employment exchange is to register people who are seeking jobs.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: You are belittling your own figures.

SHRI P. A. SANGMA; I am not belittling; I am only saying about the survey that we have conducted and I am trying to argue that the employment exchange does not give the correct figure. That is the point.

SHRI V. NARAYANASAMY; Then kindly tell us what is the correct figure, according to the survey?

SHRI P. A. SANGMA: This is just like the question, what is the correct figure of population? Like on one occasion the hon. Health Minister started[1] his speech at one point of time by giving a particular figure. After half an hour of his speech, he said: "The figure which I had given in the beginning of my speech is no more correct, because we do not know within this half an hour how? many more we have got" *(Interruptions)* So I cannot say that the exact figure of unemployment in this country is "X", it is not minus 1 or minus or plus 1. It is very difficult to say.

What we rely upon is the Plan document itself. I have made this position very clear on the floor of the House, on one occasion and I have said it. **The** National Sample Survey Organisation conducts the survey in a very scientific manner, and they place it before the Planning Commission adopts it. But, even this is not the exact figure. I must say that this is an estimated figure. I am not going to hide anything. Now, according to that survey....

SHRI RAM AWADHESH SINGH: A poorly estimated figure.

SHRI P. A. SANGMA; An estimated figure.

SHRI **RAM** AWADHESH SINGH: Poorly.

SHRI P. A. SANGMA: According to that figure which has already been given at the end of the Sixth Five-Year Plan, the backlog of the unemployment in our country was 9.20 million. The Planning

[Shri P. A. Sangma]

Commission says that during the Seventh. Five-Year Plan there will be a net addition of the unemployed people in the country to the tone of 39.38 million. This is the net addition. Therefore, during the seventh Five-Year Plan, the unemployment figure in the country will be 40.36 million. So, we will have to generate employment in our country to the tune of 40.36 million jobs. This is not a small figure. It is an alarming figure, and we are all worried about this. We will have to generate employment. As the hon. Members are aware, the Plan document also projects the generation of employment to the tune of only.. ... I am sorry, my figure is wrong. I will correct my figure.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Forty million.

SHRI P. A. SANGMA; I am sorry. The net addition is 39.38 million, and the unemployment figure will be 48.58 million,

SHRI RAM AWADHESH SINGH: The employment potential that will be created will be 40.36. So, that is a wrong figure. I challenge this figure.

SHRI P. A. SANGMA; That is the right figure.

SHRI RAM AWADHESH SINGH: Your information is wrong.

SHRI P. A. SANGMA: That is the right figure of the Plan document. I am sorry, I have to correct. The unemployment figure is 48.58 million, and the employment generation is 40.36 million.

SHRI PRAMOD MAHAJAN; How much did you generate in the first three years of the Plan?

SHRI P. A. SANGMA: The mid-term review of the Seventh Five-Year Plan is in the way. It is there. We are expecting to get the report of the midterm review very soon. Till that time, I would not venture to place any figure on the floor of the House. It will not be justified. We will have to wait. **But,** I agree with Dr. Reddy's view that whatever has been projected in the Plan document, we may not be able to achieve, because of the unprecedented drought that we have had to face. The employment that we expected to be generated in the agricultural sector or in other areas may not be achieved. I would not venture to say that this would be the figure unless the mid-term review of the Seventh Five-Year Plan is available. We are told that this would be available very soon.

SHRI V. NARAYANASAMY: What are the accepted figures quoted by you? What is the generation of employment opportunities? You come to that point also.

SHRI P. A. SANGMA: Mr. Narayanasamy, you have said that you have read the Plan document very well and came for the debate. Everything is available. Therefore, I thought I should not waste the time of the House.

SHRI V. NARAYANASAMY; What is the figure for the last three years? You kindly come to that.

SHRI P. A. SANGMA; I have already stated the generation that will be there.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: He wants to know whether there is any revised estimate of the employment generation.

SHRI P. A. SANGMA: The mid-term review of the Seventh Five-Year Plan is going on. It is almost going to be completed. We hope to get the report! very soon. Therefore, till the report is available. I would not be able to say what employment has been generated. But, I can say that as far as the rural sector is concerned, as far as the NREP and the RLEGP programmes are concerned....

SHRI RAM AWADHESH SINGH: One pertinent information.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): No please.

SHRI P. A. SANGMA: Of the last two years, I have some estimates, which, I prepared for the Governors' Conference.

I remember, we have exceeded our figure. But I am not going to give the figure because, I do not want to take any risk. We will have to wait for that review. But, may I submit to this hon. House that the unemployment problem is not confined to our country alone. Well, unemployment problem is a problem of the whole world. In fact when this was raised in the House and the Minister of Infoimation and Broadcasting had to answer this question, I was away in Geneva for a high-level meeting of the ILO discussing unemployment problem in the world. Therefore, we are not just sleeping. When you were discussing in this House. I was discussing this in Geneva in an international conference. Now, for the information of the House. I will give figures. 1 would not say I am satisfied with the figures, but I think the House should know. T will quote from the ILO Statistics book. This figure is of 1983 and somewhere 1985. It is the percentage cf unemployment to the total. "In Spain it is 22 per cent; in France it is 9.7 per cent; In Federal Republic of Germany it is 9.3 per cent, in Italy it is 10.6 per cent; in Netherlands it is 12.7 per cent; in the United Kingdom it is 11.9 per cent and in Yugoslavia it is 13.8 per cent."

SHRI RAM AWADHESH SINGH: In 'USA?

SHRI P. A. SANGMA: The USA figure is not available.

SHRI RAM AWADHESH SINGH: India?

SHRI P. A. SANGMA; India — 3.04 per cent.

SHRI RAM AWADHESH SINGH: It is a most unrealistic figure. We chal lenge it. This cannot be. It is a total ly wrong figure.

SHRI P. A. SANGMA: I will explain.

श्री राम अवधेश सिंह : इंडिया में 3 परसेंट बेरोजगार हैं और अमरीका में 7 परसेंट बेरोजगार है, यह इन्होंने कहा . . . इस बात को कौन मानेगा ? यह गलत बयानी है । सदन में आप ऐसी बात कह रहे है . . (व्यवधान) . . .

SHRI P. A. SANGMA: This is an ILO figure. Now, the point is when it is seen as a percentage to the total labour force our percentage looks small, but when you take that percentage into real number or in real terms, it is very big because the size of our population is very big *(Interruptions).*

SHRI PRAMOD MAHAJAN; Percentage is percentage everywhere. How can you say it becomes big or small with the size of population?

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमन-तप्पा) : यह फिगर्स तो उनकी नहीं है, आई० एल० ओ० का है . . . (व्यवधान)

SHRl PRAMOD MAHAJAN: That way we must congratulate the Govern ment. It is minimum unemployment here.

श्री राम अवधेश सिंह : मैं इस फिगर को सही नहीं मानता हूं, यह गलत है मेरे पास भी फिगर्स हैं . . . (व्यवधान)

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV): Mr. Ram Awadhesh Singh, this is the figure of the International Labour Organisation. It is not his figure.

SHRI P. A. SANGMA: Sir, I have admitted in the beginning that unemployment is the biggest problem in our country. *(Interruptions).*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): You ignore his internbns, Mr. Minister. *(Interrup tions),*

SHRI P. A. SANGMA: I am not taking consolation in this figure at all.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: But we cannot allow him to tell incorrect things here. How can it be 3 per cent? Even nine million comes to eight or nine per cent. Do you mean to say unemployment is only three per cent in the country?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRl H. HANUMANTHAPPA): This is an ILO figure.

SHR[PRAMOD MAHAJAN: Then, why does he refer to that?

SHRI P. A. SANGMA: It is calculated on nine million. That Ls why it is 3.04 per cent, I have said in tha beginning I am quoting the figures of 1983 and 1985 — at the end of the Sixth Plan elat the beginning of the Seventh Plan. I have not taken this figure for the entire Five-Year Plan, because in the ectii it is 48 million. So, the percentage will go up in the Seventh Five-Year Plan. I am taking it as on 1985. Please understand what I have been saying. It is on the basis of 9.20 million.

SHRI RAM AWADHESH SINGH: That is your backlog, hut by the end of tho Seventh Five Yeat Plan, your Sample Survey says... (*Interruptions).*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): He has said it. He has given all these figures.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Sir. I am on a point of order. We

श्री राम अवधेश सिंह : अमरीका का 7 परसेंट है, यहां का 3 कैसे हो सकता है? . . . इस बात को कोई सड़क पर कहेगा तो लोग हंसेंगे . . . (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमन-

SHRI P. A. SANGMA; I think so, Sir, I really don't want to go.

श्री राम अवधेश सिंह : नीतियों पर बात करिये किन नीतियों पर आप बे-रोजगारी खत्म करना चाहते हैं फिगर्स देकर झंझट पैदा होता है (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमन-तप्पा) : मिनिस्टर साहब को जवाब देने दीजिए ।

have already made our statement including Opposition Members. We had our say. Now, it is better not to interrupt the Minister

THE VICE-CHAIRMAN (SHRl H. HANUMANTHAPPA): That is the habit of Mr. Ram Awadhesh Singh. He cannol change it by sitting in the Parli 1-ment. What can I do?

SHRI P. A. SANGMA.- Sir, I am not running away from the problem. I am not taking the problem lightly.

SHRI RAM AWADHESH SINGH: I am only suggesting. This is not my habit.

SHRI P. A. SANGMA: If you wani me to compete in how to shout, I can also shout.

श्री राम अवधेश सिंह : मैं कुछ सुझाव देता हूं . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमन-तप्पा) : ऐसे पार्लियामेंट नहीं चलती है । हर रोज आपकी वजह से इतना टाइम देना पड़ता है । (व्यवधान)

SHRI P. A. SANGMA: Sir, this, as I was saying, is a very big problem. We have planned accordingly. The Plan document speaks out about generation of employment. But as Dr. Reddy pointed out we are facing an un-precedented drought. We will have to do something to achieve our target. Hut I think the real solution of the unemployment problem will not lie only in ge-nerating employment or generating development. I think the real solution will also lie in how much we are able to reduce our population. Now, employment and population are absolutely interlinked.

SHRI V. NARAYANASAMY; That is one of the factors. But that is not the main factor.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: No terruptions from that side also.

SHRI V. NARAYANASAMY: The Minister its going away from the questions put by the hon. Members. He is sidetracking the issue.

SHRI P. A. SANGMA: 1 am not side-tracking the issue. I am telling the general policy. Well, I will come to your point. Because 1 have not named you that is why you are aggrieved. One of the solutions suggested by Mr. Narayanasamy was that we must come with right to work and unemployment allowance. This is the unanimous view. Sir, this problem, this suggestion has been examined by the Government in depth very carefully. But I must say that we in the Government have come out with a conclusion that at this stage of our development it is not possible for lndia to think of giving unemployment allowance because we are a poor country, we are a developing country. We have limited resources in our country and whatever resources are available in our country, we have to invest it in productive employment. We cannot afford at this stage. I am not ruling out this possibility in future. I do not know. I am saying that at this stage of India's development, it is not possible, it is not feasible for us to give unemployment allowance to our people because whatever limited resources we have, we have to invest it for production so that it generates employment and thereby we can give them employment and not the cash benefit.

Sir, as [said there arc many things which I could say but I can only assure the House that we in the Government arc not keeping quiet about this problem. We are worried about this problem. In fact, the Prime Minister himself has said. He has been telling me. On lst of May in the Labour rally, the Prime Minister has given a commitment that it will be our endeavour to remove unemployment from this country and it is with this view that the Government is going ahead and our planning process is absolutely based on this. I thank all the hon. Members for giving a lot of ideas here. I can only keep all these idsas in mind and see where they may be vised usefully. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (H. HANUMANTHAPPA) : The House stands adjourned to meet again at 11 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at eight of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 9th December, 1987,